

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसाद अपील राख्या 01/2014

श्री लीलाराम रेगर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति रेगर निवासी रेगरों का मौहल्ला ग्राम
नौसल तहसील रुपनगढ जिला अजमेर ।अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसाद अधिकारी, अजमेर ।रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य
आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपरिथत:- 1. श्री उत्तम गुरुवक्षानी अभिभाषक अपीलान्ट
1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 07.12.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी 15 वर्षों से उचित मूल्य दुकान ग्राम नौसल तहसील किशनगढ का संचालन कर रहा था। तत्कालीन जिला रसाद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 06.08.2014 से अपीलकर्ता को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपरिथत आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपरिथत उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी 15 वर्षों से उचित मूल्य दुकान ग्राम नौसल तहसील किशनगढ का संचालन कर रहा था। अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण ग्राम नौसल के सरपंच द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाकर अपने रिश्तेदार को दिलवाने के प्रयास के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध जिला रसाद अधिकारी अजमेर को बार-बार झूठी शिकायतें प्रस्तुत की गईं। जिला रसाद अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31.8.2006 से अपीलान्ट का प्राधिकार तत्समय निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सं० 03/06 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2007 से स्वीकार कर कर जिला रसाद अधिकारी अजमेर का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल रखने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश की पालना में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। अपीलान्ट अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसाद सामग्री का वितरण कर अपने परिवार का जीवन यापन करता रहा। वर्ष 2011 में गाँव के सरपंच द्वारा पुनः अपीलकर्ता की झूठी शिकायतें कराई गईं। इन झूठी शिकायतों पर जिला रसाद अधिकारी, अजमेर द्वारा



07/12/16
जिला कलक्टर
अजमेर

विभागीय प्रकरण सं० 8/11 व 9/11 दर्ज कर नोटिस जारी करने पर अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बाद सुनवाई आदेश दिनांक 3.05.2011 में यह स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्ता रणजीतसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत नोसल पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्व में भी उनके द्वारा अपनी जाति के किसी व्यक्ति को राशन की दुकान दिलाने के लिए लीलाराम की शिकायत की गई जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो जिला कलक्टर अजमेर के आदेश पर बहाल किया गया। श्री रणजीतसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत नोसल द्वारा हमें व्यक्तिगत रूप से लीलाराम का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाने हेतु कहा गया। जिला रसद अधिकारी के इस निर्णय दिनांक 03.5.2011 के विरुद्ध श्री रणजीतसिंह द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर में अपील भी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 23.12.2011 द्वारा अपीलान्त के पक्ष में निरस्त की गई। शिकायतकर्ता रणजीतसिंह की इच्छा पूर्ण नहीं होने कारण उनके द्वारा अपीलान्त को परेशान करने एवं उचित मूल्य दुकान का संचालन अपीलान्त को नहीं करने देने की ठानते हुए अपीलान्त के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज करवाते हुए फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाया गया। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा राजनैतिक दवाब में अपीलान्त के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर मात्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने व जेल जाने के आधार पर प्राधिकार पत्र आक्षेपित आदेश दिनांक 6.08.2014 से निरस्त किया गया है। चूंकि विभागीय जांच में कोई अनियमितताएँ नहीं पाई गई हैं तथा फौजदारी प्रकरण में अपीलान्त के विरुद्ध अब तक charge भी Frame नहीं हुए हैं। अतः अपीलान्त के विरुद्ध राजनैतिक दवाब के तहत जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के पारित आक्षेपित आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने से अपास्त करार दिया जाकर अपील, अपीलान्त स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 6.08.2013 को निरस्त करते हुए अपीलान्त का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर को अपीलान्त के विरुद्ध बार-बार घोटाला करने, उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता करने, गाली गलौच करने एवं परेशान करने कारण समस्त ग्रामवासियों द्वारा राशन डीलर का बहिष्कार कर जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की शिकायत प्रस्तुत की गई। प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई। उपखण्ड अधिकारी की प्राप्त जांच रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि होने एवं अपीलान्त के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा दायर फौजदारी मुकदमा में बाद पुलिस तफतीश के न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। पुलिस तफतीश में भी आरोप सिद्ध पाये गये हैं। अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार नोटिस जारी कर वास्ते जवाब सुनवाई का प्रयात अवसर प्रदान कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की प्रदत्त की शर्त संख्या 2 व 5 का उल्लंघन किये जाने पर आक्षेपित आदेश से अपीलान्त को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि 1000/- (एक हजार) जब्त सरकार की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप एवं अपीलान्त द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।



07/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त के विरुद्ध समस्त ग्रामवासियों की प्राप्त शिकायत एवं बहिष्कार किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की प्रदत्त की शर्त संख्या 2 व 5 का उल्लंघन पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश से अपीलान्त को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2013 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.12.2016 को सरे सुनाया गया।



(गौरव गोयल)
जिला कलेक्टर
अजमेर